

अभि.
आदि के
हस्ताक्षर

25



समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

म0क0

/2019 पुर्नविलोकन

पुनर्विलोकन-0733/2019/विदिशा/28170

शैलेन्द्र सिंह पुत्र संतोष सिंह दांगी आयु
लगभग 19 वर्ष निवासी -ग्राम थान्नेर तहसील
व जिला विदिशा म.प्र.

श्री. सुनीलकिशोर पांडे
द्वारा आज दि. 21.06.19 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 3-7-19 नियत।

कलक ओक कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
21-6-19

.....आवेदक

विरुद्ध

सत्येन्द्र सिंह पुत्र सौदान सिंह दांगी निवासी ग्राम -
थान्नेर तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

.....अनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अतर्गत धारा 51 के तहत म0प्र0 भू-राज्य
सहिता 1959 विरुद्ध पारित माननीय अध्यक्ष महोदय मनोज गोयल
साहव द्वारा निगरानी 6309/एक/2017 में पारित आलोच्य आदेश
दिनांक 13.06.2019 को पुर्नविलोकन करने वावत ।

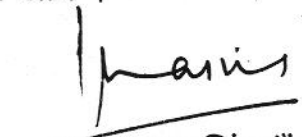
सुनीलकिशोर पांडे
21/6/19

...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 0733/2019/विदिशा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२७-८-१९	<p>यह रिट्यु याचिका मेरे पूर्वाधिकारी के द्वारा प्रकरण क्रमांक एक/निग./विदिशा/भू.रा./17/6309 में पारित आदेश दिनांक 13-6-19 के विरुद्ध दायर की गई है ।</p> <p>2/ प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर आवेदक के अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अध्ययन किया । पुनर्विलोकन का मूल आधार शैलेन्द्र सिंह के पिता संतोष सिंह द्वारा दी गई कथित सहमति पर विवाद से संबंधित है । उनके द्वारा इस सहमति से स्पष्ट इंकार किया और इसे फर्जी निरूपित किया । तहसीलदार द्वारा बटवारा नियमों का पालन नहीं किया जाना भी इस याचिका का आधार है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 27-11-2017 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-7-14 को निरस्त कर दिया इसका कुल प्रभाव यह हुआ कि अतिरिक्त तसीलदार के द्वारा पूर्व में पारित मूल आदेश दिनांक 8-8-07 अंतिम हो गया । मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने प्रकरण के सभी तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों का विश्लेषण कर दिनांक 13-6-19 को अंतिम आदेश पारित किया था । पुनर्विलोकनकर्ता ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके आधार पर यह पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार करना युक्तियुक्त प्रतीत हो। और यह भी कि याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 8-8-07 को निरस्त किए जाने के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष दीवानी दावा भी प्रस्तुत किया है ।</p> <p>3/ इन तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार किए जाने के कोई आधार विद्यमान नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये ।</p> <p style="text-align: center;">  (इकबाल सिंह बैस) अध्यक्ष </p>	